Mr. Speaker: We will now take up further consideration of the motion moved by Shri Lal Bahadur Shastri.

Shri Subodh Hansda: Sir, on a point of order.

Shri Hathi: Sir, my motion has not been put to the vote.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 and the Working Journalists (Fixation of Rates of Wages) Act, 1958."

The motion was adopted.

Shri Hathi: Sir, I introduce the Bill.

13.25 hrs.

MOTION *RE:* REPORT OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES COMMISSION—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Lal Bahadur Shastri regarding the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission. Out of five hours allotted for this discussion, two hours have already been taken.

Shri Subodh Hansda (Jhargram): Sir, I raise a point of order. It has been stated, just now that out of the five hours allotted only two hours have been taken up yesterday. Now we have got only 2½ hours left with us, which will make it 4½ hours.

Mr. Speaker: What does he want? Where is the point of order?

Shri Subodh Hansda: My point of order is that though it has been announced that five hours have been allotted for this discussion, we will now get only about four hours for the discussion of this Report. So, I would suggest that it should be postponed to the next session.

Mr. Speaker: Shri Ganpati Ram may continue his speech.

श्री गणपति राम (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय , मैं कल यह कह रहा था कि देहरादून का जानसार बाबर इलाका और मिरजापुर का पहाड़ी इलाका जिस को कि ब्रिटिश सरकार ने शैड्यूल्ड एरिया करार दिया हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने शैड्यूल्ड एरिया करार नहीं दिया है । ब्रिटिश सरकार के वक्त में उस एरिया को स्पेशल सेफगार्ड देकर के उसकी तरक्की का काम किया जाता था लेकिन हमारी सरकार जो कि वैलफेयर स्टेट कायम करने जा रही है और उसके लिये उसने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, इस इलाके को शैड्यूल्ड एरिया भी करार नहीं देती है । उत्तर प्रदेश की सरकार अपने शब्दों ही में और बैकवर्ड क्लासिज कमिशन के शब्दों में तथा शैडयूल्ड ट्राइब्ज कमिशन के शब्दों में इस बात को कबूल करती है कि उसको मान्यता प्रदान करने से एक समस्या खड़ी हो जाएगी । मैं समझता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासिस की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको साइड-ट्रैक करके, इसको दूर रख कर, इस देश के पिछड़े हुए समाज के साथ आप इंसाफ नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय , शैडयूल्ड ट्राइब्ज और शैडयूल्ड एरियाज की समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि यह तो शैक्षिक और आर्थिक समस्या ही है । लेकिन जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, उन की संख्या सात आठ करोड़ के करीब है और उन के साथ सामाजिक समस्या भी लगी हुई है, उन के साथ छुआछूत भी होता है । जहां तक शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का सम्बन्ध है , उन के साथ यह छुआ छूत की समस्या नहीं है । उनकी समस्या तो यह है कि उनका आर्थिक विकास कैसे किया जाये , शैक्षिक विकास कैसे किया जाए और यदि ये दोनों चीजें

हल हो जाती हैं तो उनकी समस्या बहुत कुछ हल हो गई समझी जा सकती है । जहां तक उन के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया हैं कि उन के लिए काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज शुरू की जानी चाहिये । हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया है । और साथ ही साथ कहा है कि जो प्लानिंग कमिशन ने इस बात को मंजूर कर दिया है कि उन के लिये १२० ब्लाक नए खोले जायें तकि उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हो सके । मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पंद्रह वर्षों में भी स्थिति का अध्ययन करने के बाद आज आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ किया जाना चाहिये । इस नाते अगले पं ह वर्ष का समय हमारे गृह मंत्री इस कार्य केंद्र लिये चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इन पन्द्रह वर्षों में भी हमारी केन्द्रीय सरकार, हमारा केन्द्रीय मंत्रालय और हमारे अफसर अगर अच्छी तरह से ध्यान देते रहें तब तो कुछ हो सकेगा अन्यथा कुछ नहीं हो जसकेगा । आपको देखना चाहिये कि जो ग्रांट दी जाए, जो लोन दिया जाए, जो फंड स्टेट्स के डिसपोजल पर रखे जायें, उनका यूटिलाइजेशन हो और पूरे तरीके से हो । आज तक तो यह देखने में आया है कि हर साल जो रुपया एलाट किया जाता रहा है, वह पूरे का पूरा खर्च नहीं होता और प्रायः देखा गया है कि प्रान्तीय सरकारें, उस में से आधा या तीसरा हिस्सा लौटा दिया करती हैं । अगर यही हालत चलती रही तो शैड्यूल्ड एरियाज और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का जो उत्थान सरकार करना चाहती है और जो एक राष्ट्रीय समस्या हमारे सामने बनी बनी हुई है, वह समस्या तो हल नहीं हो सकेगी और उसके बदले में यह समस्या और भी विकट रूप धारण कर लेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के साथ साथ अगर आप शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और शैड्यूल्ड एरियाज में खास तौर से शैक्षिक विकास करें, अगर उनको एजुकेशन दे दें, उन के अंदर समझदारी पैदा कर दें तो बहुत कुछ उन की समस्यायें हल हो सकती हैं । खास तौर से हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के मेम्बरों का ध्यान इस तरफ भी है कि उन के बीच जो नान-आफिशियल संस्थाएं काम करती हैं, उनको जो हर साल सरकार की तरफ से ग्रांट-इन-एड मिलती है' उसका ठीक उपयोग नहीं होता । इसलिए मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन संस्थाओं को जो ग्रांट-इन-एंड मिलती है उस पर ठीक तरीके से निगरानी होनी चाहिए और जो उसका ठीक तरह से यूटीलाइजेशन न करे उस के खिलाफ एक्श न लिया जा ना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनकी माली हालत को सुधारने के लिए हमारे संविधान में जो उन के लिये सरविसेज में सेफगार्ड हैं उसका पूरी तरह से इम्पलीमेंटेशन होना ही चाहिये । आज देखा जाता है कि संविधान के नियमों के अनुसार उन के कोटे को पूरी तरह से फिलअप नहीं किया जाता । सरकार ने संविधान को कार्यान्वित करने के लिये एक कम्युनल रोस्टर बना रखा है ताकि इनको सरविसेज में संरक्षण दिया जा सके लेकिन मंत्रालयों में बड़े बड़े अफसर उसका गलत तरीके से इंटर प्रिटेशन करते हैं और इन लोगो को मिलने वाली नौकरियां दूसरों को दे दी जाती हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको नौकरियां में संरक्षण देने के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए, और सरकार ने जो रिजरवेशन इन प्रोमोशन दिया है, जिसका कुछ संकेत गृह मंत्री महोदय ने भी दिया था, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जानी चाहिए ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि अगर आप उनको बसाना चाहते हैं और उनकी तरक्की करना चाहते हैं....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There are about 40 hon. Members who are anxious to speak. So, hon. Member will not take more than seven minutes.

Shri Ganpati Ram: Only two minutes more, Sir. I have some suggestions to make.

Shri Sonavane (Pandharpur): At least ten minutes should be given.

Mr. Deputy-Speaker: I have not got ten minutes to give. What am I to do?

श्री गणपति राम : केवल दो मिनट और लगेंगे ।

केन्द्रीय सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस से उन के भूमि के अधिकारों को और उन के जंगल की सम्पति के उपभोग के अधिकारों को संरक्षण मिल सके। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि संविधान लागू होने से पहले उनको जंगल की सम्पति का उपभोग करने, मछली मारने आदि के अधिकार प्राप्त थे। यदि आज वैलफेयर स्टेट उन के उन अधिकारों को भी छीन ले तो उन को कितना कष्ट होगा। इस नाते मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सलाह दे कि उनको डैट रिडेम्पशन का कानून इन लोगों को सूदखोरों से बचाने के लिये बनाना चाहिए, और लैंड लेजिस्लेशन और फारेस्ट लेजिस्लेशन पास करना चाहिए ताकि इनकी समस्याएं हल हो सकें ।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी तरक्की और विकास के लिए केन्द्र में एक अलग मंत्रालय और सचिवालय होना चाहिये जो इन चीजों की देख भाल करे और देखे कि जो रुपया इन के लिए दिया जाता है उसका ठीक उपयोग होता है या नहीं ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Dhuleshwar Meena.... Absent. Shri Sonavane. I shall be calling upon the hon. Minister to reply at 3 O'clock. Hon. Members shall not take more than seven minutes each.

Shri Sonavane: We will not be able to make any point within this period.

Mr. Deputy-Speaker: It cannot be helped. We have no time.

Shri Dasaratha Deb (Tripura East): Seven minutes only?

Mr. Deputy-Speaker: Yes. We have got only an hour and a half now.

Shri Basumatari (Goalpara): We had taken two hours only yesterday.

Mr. Deputy-Speaker: From now on we have only an hour and a half and at best only six to seven hon. Members can speak.

Shri Basumatari: Yesterday three hours were left.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Sonavane.

Shri Sonavane: Sir, at the outset I would like to congratulate the Commission on a unanimous report. The Report is well-studied and was completed and presented well before the scheduled time. The members of this Commission were eleven in number out of which five came from the Tribal communities. There was no dissident voice in this Report and I thought that the members, particularly the Tribal members, were satisfied with the findings of this Commission. Because there was no-dissenting note no separate plan or scheme was envisaged and they were satisfied with the study and this plan.

This Commission was headed by our revered Member of this House, Shri Dhebar, who is a hard worker, a good social worker and a man who has worked among he backward classes. He had put his mind, heart and soul in the work of this Commission. But I feel that if a man from the Tribal communities had been put as the head of this Commission it would have been more welcome. If the majority of the members of this Commission had been Tribals it would have given still greater satisfaction to the Tribal com-

munities as a whole. I do not cast any aspersion on the members of this Commission but I feel that if the composition of the personnel had been such, it would have been greatly appreciated.

In the note placed in our hands on the record of conclusions reached at the Conference of State Ministers in charge of Backward Classes held on the 26th and 27th July 1962 there are about 64 operative recommendations in number of which 24 have been unconditionally accepted and 6 have been accepted with some reservations. The total number of recommendations accepted comes to 30 and about the remaining 31 recommendations they have got to say something or the other. I would have been happy if all the operative recommendations of the Commission had been unreservedly accepted and implemented by the Government.

Now, I would refer to the recommendations and the conclusions of the Ministers for Backward Classes. I would first come to recommendation 4(a) which reads as follows:—

"It will be helpful if the Chief Minister is the Chairman of the Tribes Advisory Council: in any case, the Chairman should be a person who has influence over all Departments."

The conclusion reached is:—

"It was agreed that it would be very useful if the Chief Minister could be the Chairman: but the matter was left to be decided by each State Government."

I do not understand the working of the mind of the Ministers who discussed all these recommendations. Where was the harm if the Chief Minister was placed at the head of the Tribes Advisory Council? It would have added great weight and he could have understood what recommendations and schemes have been formulated, what the progress is, whether the work is accelerated or not and whether the physical targets have been achieved or not. That would have been a great asset. We know that several schemes and plans are there but there is weakness and laxity in implementing those schemes. Therefore it would have been a great asset if the Chief Minister was there as the Chairman of the Tribes Advisory Council. It should not have been left to the wishes of the State Governments. That is my observation about this.

I would now go to recommendation 12(a) which says:—

"In the States with a tribal population of one million and above there should be a Minister exclusively in-charge of the portfolio of Tribal Welfare."

The conclusion reached is:—

"The Conference was not in favour of accepting this recommendation."

I say why? It is our demand, the demand of the Backward Classes, Scheduled Tribes and Scheduled Castes, that as now there is no separate Ministry at the Centre for these people, at least. . . .

An Hon. Member: That has not been accepted by the Government.

Shri Sonavane: That is what I am referring to. I am laying stress on knowing why it has not been accepted and why there is this suspicion on appointing a separate Minister for the Scheduled Area, if not a Scheduled Tribes Minister, for a population of over a million in a scheduled Area. I think that Government should reconsider this conclusion and arrive at a very satisfactory decision in consonance with the recommendation of the commission.

Then, recommendation No. 12(d) reads thus:

"A small committee of officials from the Tribal Welfare Department and the different Development ments should be set up at the State level to ensure co-ordination and effective implementation of programmes.".

[Shri Sonavane]

I am happy that this recommendation has been accepted. But as I pointed out earlier, there is great laxity in implementation and coordination. Now that this recommendation has been accepted, I am looking forward to effective implementation and coordination and the happy consummation of all the schemes that we have laid down in the Third Five Year Plan.

Then, I find that recommendations Nos. 12 (e) and 12 (f) have also been accepted by the conference. These are intended to ensure speedy execution of schemes.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri Sonavane: I shall take just two minutes more.

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. There are about 37 Members still waiting to speak.

Shri Sonavane: There is a great sense of dissatisfaction about the non-speedy execution of schemes at present, for, unless all these schemes are speedily executed, the schemes would remain only on paper, and any haphazard or half-hearted attempt at implementation would not satisfy the people for whom they are meant, and only a lot of money would be wasted in the process.

In regard to recommendation No. 13 (b), I am happy that it has been accepted that the Governor in his report to the President should invariably give an assessment of the work of every institution which is receiving a grant of Rs. 25,000 in a year. This is absolutely essential, because at present a lot of money is wasted by the various voluntary agencies and other organisations in the course of implementation.

In regard to recommendation No. 15, I find that. . . .

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri Sonavane: I shall say just one sentence more.

Mr. Deputy-Speaker: He should conclude now. Shri Bade.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on a point of order. I want to make one submission.

उपाध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को इस सदन मे जब बाढ़ पर चर्चा चल रही थी तो बागड़ी साहब ने कहा था कि प्रधान मंत्री पर एक दिन में २५००० रुपये खर्च. . . .

Mr. Deputy-Speaker: That chapter is closed now. That point has been raised already and it has been decided upon. There is no point of order. The hon. Member should resume his seat.

Shri Ram Sewak Yadav: I am requesting the Deputy-Speaker to reconsider his ruling.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. It canot be done now.

Shri N. N. Patel (Nulsar): Why should the hon. Member take up the time of the House in this manner?

Shri Basumatari: Our time is being taken away by the hon. Member.

Shrimati Renuka Ray (Malda): This discussion should be extended to the next session.

Shri Sonavane: I have not finished yet.

Mr. Deputy-Speaker: I have called Shri Bade already. I am very sorry.

Shri Sonavane: Could I not have some time to offer some concluding remarks? The concluding remarks are very important.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may please resume his seat. Now, Shri Bade.

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिमजाति आयोग की रिपोर्ट जो कि

२० नवम्बर १९६१ को सभा की टेबल पर रक्खी गई थी, उस पर कल से सदन में विचार हो रहा है। मैं श्री ढेबर भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना परिश्रम करके ऐसी सुन्दर और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उस में उन्होंने विस्तार से आदिवासियों की तमाम समस्याओं को बड़े सुन्दर ढंग से रक्खा है और उन के समाधान के हेतु उपाय भी सुझाये हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने ढेबर भाई की रिपोर्ट को कहा है कि यह गीता और बाइबिल है। मैं भी इसको गीता और बाइबिल समझता हूं लेकिन जिस तरह से बाइबिल में हांलाकि अहिंसा का तत्व दिया हुआ है लेकिन बाइबिल के मानने वाले हिंसक हो गये हैं। उसी तरह से इस रिपोर्ट के सुझावों और सिफारिशों को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वह भी उस के विपरीत आचरण करते हैं। अब बाइबिल में तो लिखा है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो तुम उस के आगे दूसरा गाल कर दो लेकिन आज क्या हालत बन रही है ? बाइबिल के मानने वाले अहिंसा का मूल तत्व जो कि बाईबिल मे निहित है उसे छोड़ कर वाएलेंस में आ गये हैं। वे हिंसक बन गये हैं। जिस तरह से बाइबिल के विपरीत आचरण हो रहा है ठीक वही बात इस रिपोर्ट के अमल के सम्बन्ध में हो रही है। गीतावाद होते हुये भी इस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है।

अब इस रिपोर्ट में जो आदिवासी शब्द प्रयुक्त हुआ है तो यह कुछ ठीक नहीं है बल्कि इन के लिये उपयुक्त शब्द वनवासी होना चाहिये क्योंकि ये लोग वन में रहते हैं। अब इस आदिवासी शब्द से कुछ अलगाव की भावना उत्पन्न होती है जैसे कि हम और वह अलग हों। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको आदिवासी न कह कर वनवासी कहना चाहिये।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां पांच सीट्स विधान सभा में आदिवासियों की हैं और तीन सीट्स स्वर्ण लोगों की हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में मेजारिटी आदिवासियों की है। मुझे आदिवासियों के बीच में रह कर काम करने का अवसर मिलता है और मैं उनकी दिक्कतों और समस्याओं से भली प्रकार परिचित हूं। उनकी मुख्य समस्या इनडेटिडनेस और लैंडलेसनेस की है। कमिशन की रिपोर्ट में भी यही चीज कही गई है। यह लोग कर्जे में डूबे हुये हैं और उसके साथ ही भूमिहीन भी हैं। जब वह भूमि के लिये फौरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो फौरेस्ट डिपार्टमेंट उन को शत्रु सरीखा मानता है। कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फौरेस्ट डिपार्टमेंट इन जंगलों में बसने वाले आदिवासियों को दुश्मन समझता है। इसी तरह यह आदिवासी फौरेस्ट डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन समझते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। रिपोर्ट के पेज १३० पर यह दिया हुआ है :—

"We have come across cases where the forest departments have claimed as forest land on which not many trees were standing. For instance, in Spiti, they claimed practically the entire uncultivated area as forest. It was admitted to us, and we saw it ourselves, that in the 600 sq. miles of this area, there were hardly 600 trees.".

हमारे आदिवासियों ने कठोर श्रम करके और जंगलों को साफ करके मध्य प्रदेश में ३४,००० एकड़ जमीन को कृषि योग्य बना दिया है। धीरे धीरे उन्होंने जंगल साफ कर दिये हैं और वहां पर १०००० फैम्लीज बसी हुई हैं। अब आदिवासियों का मुख्य धंधा और कहना चाहिये कि एक मात्र धंधा कृषि ही है। खाली खेतीबाड़ी पर ही उनका जीवन निर्भर करता है। वहां

[श्री बड़े]

पर कोई भी स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं हैं। उनको न लुहारी आती है न सुनारी आती है न वकीली आती है और न डाक्टरी आती है। वे केवल हल चलाना और खेती करना जानते हैं। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में छोटे मोटे दस्तकारी उद्योग कायम किये जायें ताकि वे अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकें।

जंगलों को साफ करके और खेती योग्य जमीन बना कर आदिवासियों ने जिस ३४,००० एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था और जिस पर कि १०,००० फैम्लीज आबाद हैं फौरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन को इजैक्ट कर दिया है। मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने उन के झोंपड़े जला दिये हैं, तोड़ डाले हैं। उनके खिलाफ इजैक्टमेंट के केसेज चला दिये और उन के हल बैल हांक कर डिपो में ले गये। उनको बाहर निकाल दिया। मैं उन सफरर्स का एक डैपुटेशन भूपाल के मिनिस्टर के पास ले गया था।

यह इजैक्टमेंट की समस्या वहीं तक सीमित नहीं है। इगतपुरी में भी यही प्राबलम है। वहां भी आदिवासियों ने जंगल काट कर जो जमीन खेती के लायक बनाई थी और उस पर आबाद हो गये थे वहां से उनको निकाला गया। जब सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट किया गया तो बम्बई की विधान सभा में फौरेस्ट मिनिस्टर ने उन को यह आश्वासन दिया कि १९५६ तक जिनका कब्जा फौरेस्ट पर है उन को हम पट्टे देंगे। इस के लिये मैं मध्य प्रदेश में मोर्चा लेकर गया था। कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में उसी समस्या को डील किया है। इस ओर शासन को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये और उनको इस तरह बेदखल नहीं करना चाहिये। उन के पेट पर इस तरह से लात नहीं मारनी चाहिये। लेकिन प्रशासन द्वारा उधर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब वहां तो स्थिति ही दूसरी है और फौरेस्ट डिपार्टमेंट आदिवासियों को शत्रु मानता है। आदिवासियों में इस के कारण घोर निराशा और असन्तोष व्याप्त है। वे तो कहते हैं कि अंग्रेज चले गये और कांग्रेस ने हुकूमत की बागडोर सम्हाल ली लेकिन उससे हमारी हालत में कुछ भी फर्क नहीं आया। कांग्रेस सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हमारी हालत ज्यों की त्यों है।

आदिवासियों के लिये छात्रालय की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। छात्रावास में आदिवासियों के लिये जगह नहीं है। केवल २५ लड़के उनके ले लिये जाते हैं। अब बाकी लड़के क्या करें? उन के लिये कोई इंतजाम नहीं है। वहां पर उनको केवल १८ रुपये प्रतिमास का स्कालरशिप दिया जाता है जो कि बहुत ही अपर्याप्त सिद्ध होता है और उस १८ रुपये में तो उन के चने आदि की भी पूर्ति नहीं होती है। आदिवासियों के लिये स्कालरशिप की रकम बढ़ानी चाहिये। इसी तरह से छात्रावास में ज्यादा लड़कों को प्रवेश मिलना चाहिये।

फौरेस्ट डिपार्टमेंट का उन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये इस के बारे में कि कमिशन ने रिपोर्ट के १३५ पेज में यह लिखा है :—

"This class for a partnership rather than an exclusive approach which arises from the policy enunicated in 1894 and 1952 and the manner in which it has been implemented. If this change comes about, the tribal can easily be won over to the view that the Forest Department is not his enemy, but a friend interested in helping him".

कमिशन ने बहुत ही सुन्दर नोट लिखा है ताहम हम देखते हैं कि राज्यों में फौरेस्ट्स डिपार्टमेंट्स आदिवासियों के शत्रु हो गये हैं और राक्षस की तरह उनको उखाड़ कर बाहर फक रहे हैं। अब अलावा खेती के दूसरा उनके पास कोई धंधा है नहीं। उनके लिये

कोई स्मोल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं हैं। वे कर्ज़ मे डूबे हुये हैं। वे १०० रुपया कर्ज़ चाहते हैं तो शासन उनको केवल ३ रुपये तकावी के रूप में देता है, तीन रुपये कोआपरेटिव सोसाइटी से मिलते हैं और लाचार होकर उसको शेष ९४–९५ रुपये के लिये साहूकार और महाजन के पास हाथ फैलाना होता है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि वह कर्ज के बोझ के नीचे सदा के लिये दब जाते हैं। इस कारण एग्रीकल्चरल डेट रिलीफ़ बिल पास करने की मांग की जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक वह कानून पास नहीं किया गया है। रेगुलेशन के बारे में कहा जाता है कि वह आज आयगा, कल आयेगा, परसों आयगा। लेकिन उस के लिये रेगुलेशन भी नहीं निकाला गया है।

कमिश्नर आफ़ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट के पेज १२ पर लिखा है :

"That findings reveal that in the northern, central and western zones 58 per cent to 65 per cent of the tribal families were in debt. The percentage of indebted families varied from zone to zone. The worst affected zone was the western zone where the debts of over 87 per cent of the indebted families exceeded Rs. 100. The southern zone was relatively better where only 10 per cent of the indebted families were having debt over Rs. 100".

इस प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में जो सेम्पल सरवे हुआ है, उससे मालूम होता है कि उन क्षेत्रों में कितनी इंडेटिडनेस है, लोग कितने कर्ज़ में डूबे हुए हैं। प्रश्न यह है कि शासन ने इस बारे में क्या किया है। कुछ भी नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री बड़े : पाध्य महोदय, यह विषय बहुत बड़ाहै, इस लिये इन को दो मिनट में नहीं कहा जा सकता है। यह रिपोर्ट इतनी बड़ी है, जैसे गीता के अठारह अध्याय होते हैं . . .

एक माननीय सदस्य: अठारह अध्याय के लिये अठारह मिनट मिलने चाहियें।

श्री बड़े : . . . . इस लिये मैं इस पर इस प्रकार अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, जैसा कि रामायण के बारे में कहा जाता है : "आदो रामतपोवनादिगमनम्, हत्या मृगं कांचनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं एतद्धि रामायणं"।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक मेम्बर साहब ऐसा ही कहते हैं।

श्री बड़े : मैं आप के सामने दो तीन बातें रख कर खत्म कर देता हूं।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, आदिवासियों के सम्बन्ध में एग्रीकल्चर और फ़ारेस्ट की प्राबलम मुख्य है।

इस रिपोर्ट में प्राहिबिशन के बारे में बड़ा सुन्दर लिखा हुआ है। उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग उत्पन्न होते हैं कर्ज में, ज़िन्दा रहते हैं कर्ज में और मरते हैं कर्ज में। इसी तरह शराब के बारे में कहा जा सकता है कि जब वे उत्पन्न होते हैं, तो उन के मुंह में शराब डाली जाती है और जब कोई आदमी मरता है, तो उस समय भी उस के मुंह में शराब डाली जाती है। प्राहिबिशन के बाद सरकार ने कलाली की दुकानें, शराब बेचने की दुकानें, खोल दी हैं, जहां से सात रुपये में शराब मोल ले सकते हैं। लेकिन अगर वे घर में इल्लिसिट

डिस्टिलेशन करें, तो उन को छः छः महीने की सज़ा दी जाती है और वे लोग कलॉज के पजे में.फंस जाते हैं ।

प्राहिबिशन के बारे में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस को धीरे धीरे इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये, क्योंकि ड्रिंकिंग हैबिट एक दम खत्म नहीं हो सकती ।

जहां तक ट्राइबल ब्लाक्स का प्रश्न है, कहा गया है कि इस साल ७१ मध्य प्रदेश में ब्लाक्स खोले जायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े एरिया में, जिस में छब्बीस लाख आदिवासी रहते हैं, मध्य प्रदेश ७१ ब्लाक्स बिल्कुल अपर्याप्त हैं । यह भी कहा गया है कि जहां पर ६६ परसेंट इस प्रकार की पापुलेशन हो, वहां ही ये ब्लाक्स खोले जाने चाहियें । लेकिन प्रश्न यह है कि जहां शिड्यूल्ड एरिया न हो, वहां क्या होने वाला है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो काइटेरियन रखा है, वह ग़लत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री बड़े : मैंने अभी बहुत सी बातें कहनी हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: We are short of time. The number of Members wishing to speak is very large.

Shri Sonavane: Giving 7 minutes only keeps everybody hungry.

Mr. Deputy-Speaker: Then not more than two or three Members can speak.

Shri Sonavane: We cannot make our points within that time.

श्री बड़े : एक प्वायंट कह कर मैं खत्म कर देता हूं ।

इस सदन को मैं नोट आफ़ वार्निंग देना चाहता हूं कि अमरीका और जर्मनी से आए हुए फ़ारेन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जानी चाहिये । वे लोगों को दवाइयां देते हैं और धर्म सिखाते हैं । हम ने देखा है कि वे तीन चार सौ रुपये में बच्चे मोल लेते हैं । अगर फारेन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों को बन्द नहीं किया जायगा, तो आदिवासी सेवा संघ आदि सब संस्थाओं का काम फ़िज़ूल हो जायगा । मैं इंडियन क्रिस्टियन मिशनरीज़ के खिलाफ नहीं हूं । वे हमारे साथ आयें और अपना धर्म लोगों को सिखायें । हम भी अपना धर्म सिखायेंगे और हम देख लेंगे कि कौन सा धर्म बड़ा है । लेकिन, जैसा कि मैंने आप को बताया है, वे लोग तीन चार सौ रुपये में बच्चे मोल लेते हैं और उन को पढ़ाते हैं । मैं स्वयं वहां से चार पांच बच्चों को वापस भगा कर लाया हूं । इस बारे में नियोगी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यदि फ़ारेन क्रिस्टियन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों को बन्द नहीं किया जायगा, तो शासन का लोगों को कट्टर देशभक्त बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आदिवासियों में पृथकता की भावना पैदा होगी और देश का डिस-इन्टेग्रेशन होगा । इसलिये इस हाउस से मेरी बिनती है कि फ़ारेन क्रिस्टियन मिशनरीज़ के कार्य को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माणिक्य लाल वर्मा ।

श्री बड़े : मेरी बिनती है कि जिस माननीय सदस्य को बुलाया जाये, उस को कम से कम पंद्रह मिनट दिये जाने चाहियें । बाकी माननीय सदस्य सेक्रिफ़ाइस करने के लिए तैयार हैं ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे होम मिनिस्टर साहब के भाषण और ट्राइबल लोगों के बारे में उन की घोषणा से हम को संतोष हुआ । उस में एक कमी रह गई है, जिस का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है और वह है फ़ारेस्ट कोआपरेटिव सोसाइटी । आदि-

lication of 'Gram –

वासियों में पूरी खेती की जमीन नहीं है और वे लोग पहाड़ियों में रहते हैं । उनकी सारी इकानोमी और आर्थिक व्यवस्था का दारोमदार जंगलों पर ही है । अगर उन के जीवन-निर्वाह का कोई ज़रिया हो सकता है, तो वह फ़ारेस्ट है ।

जैसा कि कल डा० उइके ने कहा, फ़ारेस्ट्स के बारे में स्थिति यह है कि राइट्स को कनसेशन में बदल दिया गया है । और वह दरअस्ल था राइट । आज यह कहा जा रहा है कि जंगलों का विनाश हो गया लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों का विनाश हुआ है ठेकेदारी प्रथा से । पहले जंगलों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं था । जो कुछ भी उस की आमदनी थी, उस का लाभ आदिवासी लेते थे । १८८४ में उस को कानून की शक्ल दी गई और उन राइट्स को कनसेशंज और प्रिविलेजिज में बदल दिया गया । आज उन लोगों को बहुत परेशानी है । अगर आदिवासियों को यह पता हो कि जिस जंगल में वे रहते हैं, जिस को उन्होंने सदियों से उगाया है, वह हमारे लिये नहीं है, तो चाहे कितने भी फ़ारेस्ट गार्ड्ज रखे जायें, और उन्हें उस जंगल में कुल्हाड़ी नहीं ले जाने दी जाये फिर भी दरख्त को पैदा नहीं होनें देंगे । वे लोग यह कर सकते हैं । लेकिन जिस समुद्र में वे रहते हैं, उस में उन को पानी पीने का अधिकार नहीं है । वहां से उन को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती, मकान के लिये लकड़ी नहीं मिलती. मुर्दा जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती । आदिवासी यह मानता है कि :

चमन को इसीलिये माली ने खूं से सींचा था
कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें ।

आदिवासी को इस बत का पता नहीं था कि उसने जो जंगल खड़ा किया है उस का लाभ उस को नहीं मिलेगा, अगर उस को यह पता होता, तो वह कभी दरख्त पैदा नहीं होने देता ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट चालू होनी चाहिये और ठेकेदार जंगलों से निकाल दिये जाने चाहियें, और उन्हें जंगल का कोई ठेका नहीं देना चाहिए । अगर संविधान में हम ने समाजवाद की स्थापना की व्यवस्था की है, , समाजवाद का नारा लगाया है, तो उस के लिए यह ज़रूरी है कि सैंटर की तरफ़ से स्टेट्स के नाम यह आर्डर जाना चाहिए कि कोई ठेकेदार जंगलों के लिए नहीं रहेगा और वह काम आदिवासियों के कोआपरेटिव को दिया जायेगा ।

लेकिन केवल को-आपरेटिव सोसायटी ही काफी नहीं है । डा० राम सुभग सिंह को हम ने लिखा था कि जंगल को-आपरेटिव्ज को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ़ से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जंगल को एग्रीकल्चरल परपज ही नहीं माना है । मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है । अगर फ़ारेस्ट नहीं होगा, तो खेती कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा ? चूंकि फ़ारेस्ट को एग्रीकल्चरल परपज नहीं माना गया है, इस लिए को-आपरेटिवज को न तो बैंक से और न स्टेट से ही कोई कर्जा मिलता है । आदिवासियों के पास पैसा नहीं है । । जो १७ हज़ार २० हज़ार, ५० हज़ार की रायल्टी ली जाती है, वह आदिवासी बेचारा कहां से लाए ? इस लिए मेरी दरख्वास्त है कि फ़ारेस्ट को-आपरेटिव सोसायटी को लोन मिलना चाहिए, चाहे वह बैंक से मिले, स्टेट से मिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिले, कहीं से मिले, लेकिन लोन ज़रूर मिलना चाहिए

इस के बाद प्रासेसिंग इंडस्ट्री का प्रश्न भी आता है । आज खादी ग्रामोद्योग कमीशन में एक नियम है कि वह खादी के सरंजाम का पैसा देता है । सरंजाम के माने हैं चर्खा और अम्बर चर्खा । आज हजारों तहसीलों में जंगल

[श्री मा० ला० वर्मा]

नहीं हैं और इसलिये किसानों को खेती के औजार लकड़ी के मिलते नहीं हैं। फारेस्ट की कोआपरेटिव सोसायटीज हल, जुआ और चौ आदि खेती के औजार, एग्रीकल्चरल-इम्प्लीमेंट्स, बना कर बेचे जायें, तो लाखों रूपये का लाभ उन्हें हो सकता है।

खादी ग्रामोद्योग कमिशन खेती औजार बनाने के कारखानों को ग्रामोद्योग में शुमार नहीं करता है। कोई भी नहीं मानता है। इसलिए यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि इस उद्योग को लोन मिलें और उनकी सोसाइटीज को तीन साल तक करीब करीब सहायता मिले और अगर वहां पर कोई टैक्नीकल आदमी रहे तो उसका खर्चा भी तीन बरस तक सोसाइटी को सरकार फ्री दे। जितना आपका यह फरनीचर है और जितनी लकड़ी का इस हाउस को बनाने में प्रयोग किया गया है यह सारी की सारी लकड़ी वहां से सप्लाई की जा सकती है। आदिवासी जितना फरनीचर है, जितनी इमारती लकड़ी है, जितनी गोंद है, शहद है, मूसली है, वनस्पति है, आयुर्वेद की औषधियां हैं, जितनी भी यें चीजें हैं, सप्लाई कर सकते हैं। अगर इनको लेने की व्यवस्था हो जाए तो तो उनका शोषण बन्द हो सकता है। मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के साथ साथ जो उसकी प्राग्रेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वे भी चालू की जानी चाहियें ताकि उनको राहत मिल सके।

14 hrs.

माननीय श्री बसुमतारी साहब जो कि कमिशन के मैम्बर थे इन्होंने मुझे याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश में फाइनेंस कोआपरेटिव एंड डिवेलेपमेंट कारपोरेशन है जो कि आदर्श रूप से कार्य कर रही है मैं इसको मानता हूं कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वहां आदिवासी अपनी बनाई हुई चीज लाते हैं और उस के बदले जिस चीज की उनको आवश्यकता होती है, ले जाते हैं। वे शहद लाते हैं। और उसके बदले में उनको अगर कपड़ा चाहिये होता है तो कपड़ा ले जाते हैं, गोंद लाते हैं, उसके बदले अगर उनको नमक चाहिये होता है तो नमक ले जाते हैं। इस प्रकार से आदिवासियों का जो शोषण है वह वहां बन्द हो गया है। हिन्दुस्तान में शोषण-मुक्ति का का अगर कहीं कोई नमूना आपको देखना हो तो आप आंध्र में जा कर देख सकते हैं। उसी प्रकार की कारपोरेशंज सारे हिन्दुस्तान के आदिवासी क्षेत्र में आप बनां दें। मैं तो कहूंगा कि हर दस हजार की आबादी जहां हो और जहां पर जंगल हों वहां एक एक कारपोरेशन बना दिया जाना चाहिये ताकि आदिवासियों को राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि जब तक ठेकेदारी प्रथा का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन में अगर कोई मनहूस डिपार्टमेंट है तो वह फारेस्ट डिपार्टमेंट है। हिन्दुस्तान में जहां जहां भी हमारा कमिशन गया, वहां पर उसको यह चीज देखने को मिली। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि यही एक कमिशन ऐसा था जो ढेबर भाई की अध्यक्षता में बिठलाया गया था जो कि पैदल घूमा है। जितने भी दूसरे कमिशन इस देश में कायम हुए हैं वे राजधानी तक ही गए होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज तक ही गए होंगे मगर हमारा जो कमिशन था वह २८-२८ मील पैदल गया है, जंगलों में जा कर घूमा है। किसी भी कमिशन का चेयरमैन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पैदल गया हो। गांव गांव और जंगल जंगल भटका है और वहां पर इसने धूनी रमाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री मा० ला० वर्मा : आप कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊंगा। मेरी तो दरख्वास्त थी कि समय को आप बढ़ायें। फिर भी कुछ बातें कह कर समाप्त कर दूंगा।

जितनी भी नान-आफिशल एजेंसीज हैं, उन को काम करने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं कालेजों के लड़कों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं, व साल साल बाद मिलती हैं। उन्हें एडवांस मिलने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं आपको राजस्थान की बात बतलाना हूं। वहां पर कालेज में दो लड़के पढ़ने के लिए गए, एक टैक्नीकल साइड में गया और दूसरा एग्रीकलचर साइड में। इन दोनों को साल भर छात्रवृत्तियां नहीं मिलीं और इसका नतीजा यह हुआ कि वे बेचारे वापिस आ गए, वहां पर टिक नहीं सके। टिक भी कैस सकते थे ? उन के पास इतना पैसा ही कहां होता है। छात्रवृत्तियों का ठीक इंतजाम नहीं है। मैं चाहता हूं इस ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिये। साथ ही साथ जो नान आफिशल एजेंसीज हैं, उनको साल साल या छः छः महीने के बाद पैसा मिलता है। क्यों नहीं उनको एडवांस पैसा दे दिया जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये जो छात्रवृत्तियों में कंजूसी दिखाई जाती है, और कमी की जाती है यह भेद भाव बन्द होना चाहिये।

मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूं। एक जगह हमें एक साहब ने कहा कि इन छात्रों के लिए खाट क्यों देते हो, चारपाइयां क्यों इनको देते हो, इनकी आदत इस से खराब हो जाएगी। मैं ने उन से कहा कि तुम्हारे बच्चे जब खाट पर सोते हैं तब तो उनकी आदतें खराब नहीं होती हैं लेकिन जब ये सोते हैं तो इनकी आदतें खराब हो जाती हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासियों के पास आपको बिस्तर चाहे न मिले, कपड़ा चाहे न मिले, लेकिन खाट जरूर मिलेगी।

उनको सामान देने में जो कंजूसी बरती जाती है, मैं चाहता हूं कि यह भी बन्द हो। जहां तक नान-आफिशल एजेंसीज का सम्बन्ध है, उन के बारे में भी, आप थोड़ी सी उदारता दिखायें। उन के वक्त पर और अच्छा पैसा मिलना चाहिये।

आप घंटी बजाते जा रहे हैं जिस के कारण मुझे अपना भाषण समाप्त करना पड़ रहा है और मेरे दिल के जो अरमान हैं, व दिल में ही रह जाएंगे। इस वास्ते मैंने पहले ही दरख्वास्त की थी कि और अब फिर करता हूं कि इसको आप लम्बा बढ़ायें और हमें काफी समय बोलने के लिये दें। अब जितना समय दिया गया है उस में अधूरी बात ही मैं कह सका हूं और सारी की सारी मांगों को आपके सामने पेश नहीं कर सका हूं।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी इस जनतंत्र की सरकार ने पंद्रह साल के भीतर इन शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर एक कमिशन बिठाया और एक रिपोर्ट तैयार करवाई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह गीता है। जिस तरह से गीता को कोने में रख दिया जाता है उसी तरह से इसका भी किसी कोने में न रख दिया जाए, इसका मुझे बहुत डर है, ऐसी आशंका मुझे होती है। यह जो रिपोर्ट है यह इतनी डिटेल्ड है और इतनी डिटैल्ड स्टडी के बाद इसको लिखा गया है और इतनी ज्यादा रिकमेंडेशंज इस में दी हुई हैं कि मुझे शंका होती है कि शायद हमारी सरकार इसको कार्यान्वित भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी।

एक बात जो मैंने इस रिपोर्ट में देखी और जिसको मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं यह है कि इस में यू० पी० का नामोनिशान नहीं है। हालांकि थोड़ा सा रिपोर्ट में माना गया है लेकिन वहां की सरकार उसे नहीं मानती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाके की बैगा, चेरो, गोंड, मझवार, खखार, भुइयां, पनिका, कोल, धांगर और देहरादून उत्तरकाशी की जौनसार, बवारस जातियां शैड्यूल्ड ट्राइब्ज में आती हैं। मैं इस कमिशन के चेयरमैन ढेबर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी विस्तृत थारो स्टडी कर के यह रिपोर्ट बनाई है और इस में कोई शक नहीं है कि इसके लिए उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है।

[श्री विश्राम प्रसाद]

उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को जब मैं देखता हूं तो मुझे अमरीका के रेड इंडियंज की याद हो आती है। रेड इंडियंज को अमरीकनों ने लड़ाई के जमाने में मार मार कर जंगलों में भगा दिया था और इसी तरह से यहां के आदिवासियों का भी घर बार जंगल ही है। लेकिन रेड इंडियंज का वहां जो जंगल है, उन के ऊपर पूरा अधिकार है, वे जंगलों को लकड़ी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उस के अन्दर जो भी मिनरल्ज निकल सकते हैं, उस पर उनका अधिकार होगा लेकिन यहां भारत के आदिवासी जंगलों में तो रह सकते हैं लेकिन वहां पर उनका कोई किसी किस्म का अधिकार नहीं माना जा सकता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगल की कोई भी सामग्री वे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह दोनों में अन्तर है।

पापुलेशन जो इस में उनकी लिखी हुई है, वह २,२५,११,८५४ यानी ६.२३ परसेंट लिखी हुई है। इस में यह भी बताया गया है कि इन में से ९०.५ परसेंट आदमी खेती में लगे हुए हैं। मैं ज्यादा इस के बारे में कुछ नहीं कह कर जो इनकी वित्तीय हालत है, जो कर्जा इन के सिर पर है, उस के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं।

राजस्थान में कर्ज का नाम सगरी है, आंध्र में बेटी है, उड़ीसा में गांधी है, मैसूर में जीधा है, मध्य प्रदेश में नौकरी नामा है जिन लोगों को कर्ज दिया जाता है और जो उस कर्ज के बदले में आते हैं, उनको कहीं कहीं खाना दिया जाता है और कई-कई सालों तक, जिन्दगी भर तक और यहां तक कि तीन तीन पुश्तों तक वे कर्ज में डूबे रहते हैं। किसी ने या किसी के ऐंसस्टर्ज ने अगर दो दो सौ रुपया कर्जा भी ले लिया तो उसके लड़के और लड़के के लड़के यानी पोते तक बराबर उस कर्ज के बदले में नौकरी करते रहेंगे और उनको इसके बदले में सिर्फ खाना मिलेगा और साल में २५ रुपये मिलेंगे। इसक मतलब यह हुआ कि दो रुपया महीना यानी एक आना रोज। इस सदन में एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो आने मजरी का जिक्र किया था तो बहुत से माननीय सदस्य ने हल्ला मच्चा दिया था लेकिन इस जनतंत्र देश में ऐसे आदमी भी हैं, जो कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी और राम राज्य रूपी भारत में आज भी एक आना मजदूरी पाते हैं। यह बहुत भारी शर्म की बात है।

अब मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि कितने परसेंट ये लोग कर्ज से लदे हुए हैं। बिहार में ९० परसेंट कर्जे से लदे हुए हैं। केरल में सौ परसेंट दबे हुए हैं। मसूर में तीन सौ फैमिलीज हैं जिन के बारे में बतलाया गया है कि कर्ज जिसे 'जीठा' कहते हैं, जिन को कई पुश्तों से कर्जों तक बदले में काम करना पड़ रहा है। मद्रास में २००० से २५०० तक प्रति फैमिलीज पर कर्जा है। पश्चिमी बंगाल में सौ से डेढ़ सौ रुपया या दस से पन्द्रह मन अनाज कर्ज फी फैमिली है। आंध्र प्रदेश में पचास रुपये फी फैमिली है। क्योंकि यह फिगर वहां की जिला परिषद् ने दी है जोकि कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। असम में ६६ परसेंट परिवार कर्ज में हैं, मध्य प्रदेश में प्रति परिवार १३० रुपया कर्जा है, पंजाब में ७० परसेंट परिवार कर्जे में हैं और प्रति परिवार १००० रुपया कर्जा है। राजस्थान में प्रति परिवार १८० से २४० रुपया कर्जा है। तो यह कर्जे की स्थिति है। इस में कर्जे के दावेदार के लिये कहा गया है कि वह समय पर केस दायर करे, अपने कागजात दिखलाये, अगर सबूत न हो तो केस खारिज कर दिया जाए, जबानी गवाही न मानी जाये, सूद की उचित दर तै की जाए और सिम्पिल इंटरेस्ट लिया जाए। लेकिन सोचने की बात है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं। सरकारी संस्थाएं उनको कर्ज नहीं देतीं। इस कारण वे इन सूदखोरों से दबे रहते हैं। अगर सरकार उनको कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिए

या अन्य तरीके से आसानी से कर्जा देने की व्यवस्था कर दे तो इन की कर्ज की व्यवस्था सुधर सकती है ।

यह बताया गया है कि इन की शिक्षा के लिये पहली योजना में ५ करोड़ १० लाख रुपया, और दूसरी योजना में ८ करोड़ २१ लाख रुपये रखा गया जिस में ११४ लाख खर्च नहीं हो सका और बच रहा। लड़कों को शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता है और उनको वजीफे दिए जाते हैं। ये सभी बातें हैं लेकिन देखना यह है कि शिक्षा पाने के बाद उनको नौकरी कैसे मिलती है। स्टेट व यूनियन पबलिक सरविस कमीशन का एडवरटाइजमेंट कैसे होता है उस में लिखा रहता है :—

"The post is reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If suitable candidates are not coming from them, it will be treated as unreserved."

इसको पढ़ कर आप समझेंगे कि इन लोगों के लिए सरकार बहुत कर रही है, लेकिन वास्तव में होता क्या है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की कितनी सीटें भरी जा चुकी हैं, उससे आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। जनता के सामने दिखाया जाता है सरकार बहुत कर रही है लेकिन वास्तविकता और है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आई० ए० एस० में सन् १९५५ में एक आदिवासी लिया गया, सन् १९५६ में १ लिया गया, सन् १९५९ में २ और सन् १९६० में ५ लिए गए । इस तरह आज तक कुल ९ आदिवासी आई ए० एस० में लिए गए हैं, और आइ० पी० एस० में केवल ३ । इसके अलावा आप देखें कि क्लास १ की ११,३७८ जगहों में से २३ आदिवासियों को मिलीं, क्लास २ की २२,२१३ जगहों में से इनको १६२ जगहें मिलीं और क्लास ३ की ८,६९,२२१ में से आदिवासियों को ८,१६८ जगहें मिलीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपको इन लोगों को इनका उचित स्थान दिलाना है तो पोस्ट एडवरटाइज हों .

Mr. Deputy Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, he must be given 20 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: This is not done according to the parties.

Shri Surendranath Dwivedy: It is always given to the Opposition; it may not apply to that Party. If you do like this, it will be a departure from the usual practice.

Mr. Deputy-Speaker: Nobody has taken more than ten minutes; even the Communist Party Members have not taken more than that.

Shri Surendranath Dwivedy: I am not saying about the Communist Party; I am saying that he should be given more time.... (*Interruptions*).

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, in all discussions of this nature, or even otherwise, time is apportioned as between the Congress Party Benches and the Opposition as a whole.

Mr. Deputy-Speaker: I am talking of Opposition as a whole.

Shri Surendranath Dwivedy: Let us know how much time has been taken and how it has been divided..... (*Interruptions*).

Shri Basumatari: One hour is taken by the hon. Members. The Chair is not responsible for that, if Members take more time. Some Members are responsible for that and they do not also allow the discussion to proceed.

श्री विश्राम प्रसाद : तो मैं कह रहा था कि अगर आप नौकरियों में इन लोगों को उनका उचित स्थान देना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करना चाहिए कि इन लोगों के लिए इतनी सीटें हैं और इतने कैंडीडेट चाहिए। सरकार को इस विषय की

[श्री विश्राम प्रसाद]

पीछे नहीं डाल देना चाहिए । अभी हमने देखा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को आगे के सेशन के लिए डाल दिया गया और कल से जो यह रिपोर्ट चल रही है इसके लिए भी कहा जाता है कि इसको हटा दिया जाए और आगे लिया जाए । आपको अगर महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा करना है तो आदिवासियों को नौकरियों में उचित स्थान देना चाहिए । केवल रिपोर्ट बना देने से कोई काम नहीं चल सकता और न उनकी समस्या हल हो सकती है । आपको इस बारे में दृढ़ता से कदम उठाने चाहिएं जिसमें इनकी तरक्की हो सके । केवल रिपोर्ट बना देने से मतलब हल नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : पर रिपोर्ट भी होनी चाहिए ।

श्री विश्राम प्रसाद : अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

इन लोगों की शिफ्टिंग खेती होती है । कुछ समय से ये लोग एक जमीन पर खेती करते हैं और कुछ समय बाद दूसरी पर । फारेस्ट विभाग कहता है कि इससे साइल इरोजन होता है । मैं किसान होने के नाते कहता हूं कि साइल इरोजन नहीं होता । जब उस जमीन पर घास जमी हुई है तो साइल इरोजन कैसे हो सकता है ।

जमीन पर इन लोगों का अधिकार होना चाहिए । उनको बीज की, खाद की, फरटीलाइजर की सहूलियतें मिलनी चाहिएं उनके लिए लैंड टेन्योर सिस्टम में सुधार होना चाहिए ताकि उनका जमीन पर अधिकार रहे । जंगल के जो उनके अधिकार हैं वे सुरक्षित रखे जाने चाहिए ।

उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं । यह ठीक ही है । इसमें दो राए नहीं हो सकतीं ।

फारेस्ट प्रोड्यूस पर उनका जो अधिकार है वह उनको मिलना चाहिए । यदि वे लोग ठेका ले सकें तो किसी अन्य ठेकेदार के मुकाबले उनको ठेका मिलना चाहिए । ये ठेकेदार लोग आ कर ठेके लेते हैं, इन लोगों से ही काम करवाते हैं और इस सिलसिले में इनकी औरतों के साथ व्यभिचार आदि होता है और अन्ततः ये गरीब के गरीब ही रहते हैं ।

इसके अतिरिक्त वहां कुछ उद्योग चलाए जा सकते हैं जैसे शीप फारमिंग, एनीमल हसबेंडरी आदि हैं जिनसे उनकी आर्थिक दशा सुधर सकती है ।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के दफ्तर के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मैं उसको पोस्ट आफिस कहता हूं । अगर उनको कोई अर्जी दी जाती है तो वह फारवर्ड कर देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता । इतना काम तो हम किसी मिनिस्ट्री के द्वारा भी करवा सकते हैं ।

अन्त में मेरी यह प्रार्थना है कि अगर आपको कुछ इनके लिए करना है तो हृदय से करिए । श्री दातार इस समय यहां नहीं हैं । मेरा उनके लिए एक सजेशन है । उनको चाहिए कि बजाय इस मिनिस्ट्री में काम करने के उनको शिड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर के काम में लग जाना चाहिए, उसमें वह ज्यादा काम कर सकेंगे ।

Shrimati Renuka Ray: Mr. Deputy Speaker, I think it is necessary for us to remind ourselves, before we discuss this report, why this Commission was appointed. Article 46 of the Constitution says that "the State shall promote with special care the education and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the Scheduled Castes and Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." Article 339 speaks of this Commission to review the progress. This Commission sent in its report in October 1961. Every one will acknowledge that under the leadership of Dhebar Bhai this Commission has given a very extremely thought-provoking report. They have studied the subject in great detail. I think it is scant courtesy that we give to the authors of this report

and to this House itself that in the last hour of the last day of this session we are discussing this report and the time that is given to it is being reduced. I am not blaming the Minister in charge. But the Home Ministry should have insisted that this matter is of such great importance that we should not deal with it in this scant fashion. The Commission has taken so much trouble to draw up this report. The House should take proper counsels and get the suggestions implemented. I say this more because there have been committees earlier which have dealt with this problem . . .

Mr. Deputy Speaker: I think the hon. Member will do well to come to the report. This matter has been raised earlier and the hon.. Speaker had also mentioned about it.

Shrimati Renuka Ray: I know. I will come to the point. I merely say that there is very little time to go into the details. I am merely making one or two points about the report. First of all, there have been many reports in regard to some of the aspects of this Commission's report. Therefore, I am all the more diffident as to whether the implementation of this report will take place. But I hope that at least considering the stature of the chairman of this Commission, the recommendations of this Commission will be implemented properly. But as I said, there have been many committees and commissions which have touched on many of the problems contained in this report, and indeed, we have discussed here the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes year after year, and yet we find that the essential things are not implemented. I do not say that no work has been done. That would be wrong. But I say that the manner in which the work is implemented does not bring about the objectives which I just now read out.. We want to improve the conditions of the people so that there should be national integration. But we do not want to impose anything on them. This has been stated in the report of the Commission, and yet the manner in which we approach the subject, the way in which it is implemented, is not satisfactory. I am afraid we are trying to segregate these people more and more. I do not say that Scheduled Areas should be given up. But I do say that the whole objective of bringing about improvement, economic and social, in the Scheduled Areas and among the Scheduled Tribes should be carried out in such a way that they should gradually come into line with the national development of the country as a whole.

That is not done. I do not say that the money allotted for this purpose is less. I know there are large sums given. But the sum is not always spent in the way it ought to be spent. This report has pointed out that there is an attempt on the part of many State Governments to think that this money is not used to supplement but is the total amount spent on the Scheduled Tribes. On the other hand, what is required is that this amount should supplement the help that tribals also get from what is being done for the general development.

The time at my disposal is very little and I shall make only a very few points. I think the economic criteria should be established not only in regard to the Scheduled Tribes as a whole but in regard to the different layers of Scheduled Tribes as has been mentioned in the report of the Commission. At the beginning of the report, the Commission says:

> "Amongst the tribals also we have been able to notice four different layers. At one stage we were thinking of preparing a list. For lack of adequate data, however, we dropped the idea."

They have said that the topmost layer of these people are not in need of help, but yet, if you go into some of these reports, you will find that the scholarship and other measures of improvement go to the topmost layer. Though they are able to help themselves, they get more help than

[Shrimati Renuka Ray]

the lowest layers among themselves who are the most backward among the Scheduled Tribes. Unless we can utilise the funds among the lowest layers of these people in order that they come into line with the rest of the people as a whole, the money that is being spent on them will not have been spent in the right way.

Another point that I wish to make is about land. The whole policy regarding land for the tribals is something that is pathetic if not very tragic. It is a pity that we should even now allow this policy to continue. It is still a fact that the Scheduled Tribes are being gradually deprived of their land. There is no doubt about it. In the name of doing away with shifting cultivation, etc.,—I cannot go into the details—it is true that to a large extent they have been deprived of their land. Not that any one wanted to do so, but it so happened. It is essential that the report of the Commission in regard to this matter—it has gone into great detail—should be implemented. If the Government is not able to do that, then it is no use having this Commission appointed or having other such committees appointed either. How can exploitation be stopped unless we have a proper land policy in regard to the Scheduled Tribes as well. The Commission has stated that all the land that is cultivatable should be utilised to the extent possible and that land should go to the Scheduled Tribes, in the areas where they live. I hope this suggestion will be implemented by the Centre and the State Governments.

There are many other points. I can give one instance. I happened to have the privilege of going about the country to study certain matters including the problems of Scheduled Tribes. In one place, the Scheduled Tribes were undertaking jhoom cultivation and they were cultivating in common with each other, and in cooperation with each other. But they did not know the word "cooperative". On the one hand, we are talking of co-operation and asking the people to go in for co-operatives. On the other hand, we try to give them individual rights on land and we want to take away the whole fabric of the structure on which they would build the co-operative idea without knowing what is meant by co-operative act as we know it. These are some points which have got to be remedied.

I merely want to say that the time that has been given to the discussion of this report is extremely short and inadequate. I hope that the Government will see to it that due respect is shown to this report which has been prepared under the chairmanship of Shri U. N. Dhebar and that the recommendations will be implemented. Unless the recommendations are implemented, there is no reason whatsoever to waste the time of some of the most distinguished people of this country who have given so much time and energy to produce such a report. I hope the Government will see to it that not only the minor matters but all the matters that have been touched upon and on which recommendations have been made are implemented.

For implementing the recommendations, in the first place, you have to understand the tribals and their psychology. Unless you do that, you cannot carry out the work, however much your policy is right. The trained personnel employed should understand the tribals and then alone we can bring them into line with the general community as a whole.

Shri Dasaratha Deb (Tripura East): At the tag-end of this session, we are discussing this very important item. The time is very short and we are not in a position to express our mind freely and leisurely, or even to make some remarks on the recommendations made by the Commission. I agree that this Commission has suggested many valuable points which are worth following. If those suggestions are implemented, that will help our people. But I must say, at

the same time, that this report suffers from some sort of realsitic approach to many aspects of the tribal problem.

First, I must say that this report has largely touched upon the administrative problems only. While one has to find solutions to administrative problems and make suitable arrangements, we must have the other approach also, namely, the culture and tradition of the tribal people, and also the political power of these people. Unless you give these tribal people the political power and a share to participate in the management of their own affairs, they cannot be helpful and even the good wishes of the Government and the Commission will not be of any avail.

In this respect, I would like to say that the Dhebar Commission has suggested that certain areas should be declared as Scheduled Areas and the transfer of land and other things should be absolutely banned. A suggestion was also made to the effect that Scheduled Areas should be defined. How to define these areas? It still remains. Yesterday, the Home Minister said that those areas in which there is more than 50 per cent of tribal people may be declared a Scheduled Area. Even then, how can this be defined? If you take the tribal belt alone, there will be more than 50 per cent or even cent per cent tribal population. If you take a tribal belt along with other big areas, you would not find more than 50 per cent., but only less than 20 or 30 per cent or less.

Take, for instance, my State, Tripura. This idea of Scheduled Areas is not a new thing. It is as early as 1341 Tripura Era. It is now 1372 Tripura Era. In 1341 Tripura Era, the Maharaja had declared certain areas as tribal areas. Of course, some portions were taken out, as a necessity, for the rehabilitation of refugees. I agree with that idea, but still, the remaining portion has not been defined. I have been fighting both in the Advisory Committee and also here in Parliament that the administration of Tripura should define this area and that it will have to be well demarcated. The best way to locate these areas is to have the demarcation posts or digging earth line. Now, what has happened is, redivision of *maujas* and regrouping have taken place. The whole tribal belt and the tribal population have been split up in so many factions and each fraction of the the tribal areas have been joined with certain other areas which are non-tribal, and thus, the strength of tribal population in the new regrouped *maujas* has been decreased, and the tribal areas also decreased.

Now, even when the panchayat constituency was formed, one of our main demands has been that in the absolutely tribal belt there should be a separate constituency where the tribal population is in a majority. The argument was put that because there is no tribal majority area, and one portion of the Mozas should not be linked up with another portion of the Mozas and they should not be formed into one single constituency. That was the argument advanced, and now that thing also has not been done. That is why I say that the tribal area should be made into a separate administrative unit. I do not say that it should secede from the existing State; it should be in that State. But for the administration of the tribal areas, a separate administrative arrangement must be there.

And I suggest that in all the tribal areas there should be a Tribal Development Council, and that Council should be purely elected bp the tribal people on the basis of adult franchise; and all development works, including the management of lands and other things that we have been suggesting here should be given to that Tribal Development Council, and it should not be given to others. That point should be noted here very clearly.

Secondly, the hon. the Home Minister said yesterday that it is a question of getting trained personnel. How

[Shri Dasaratta Deb]

can you get trained personnel if you do not give them education and other facilities? I know in Tripura you do not get any trained personnel. In my area in Tripura State I know that so many non-tribals have been recruited. The Government have spent so many lakhs of rupees for work in the under-developed areas. After going there, their trained cadres just try to get their salaries and so on. That is all, and there is corruption and other things.

That is why I have made the suggestion again and again in this House. What is happening? For your social work and other services you say that you want matriculate. Matriculation is made the minimum qualification. No tribal people have been recruited in our parts because they are not matriculates. I suggest that non-matriculates and other people must be given their chances also.

My time is very short and so I cannot make my points in greater detail. But I suggest that wherever it is possible, particularly in the eastern sector of India, in Assam, Tripura, Manipur and other places, a separate administrative unit or units in each of those States should be formed comprising only the tribal area. It is possible, and that is why I request the Government of India to consider that matter and give their thought to have that type of administration there.

The tribal people of Assam are demanding a separate State—I do not know how far it is correct or not; I am not going into that question. But one fact remains, namely that these tribal people were not satisfied. Because, if they were satisfied, how is it that after their remaining under Congress rule for fifteen years, this question has suddenly come up? We must agree, therefore, that there must be some discontent, some dissatisfaction and exploitation going on in that part of the country, and that is why there is this demand.

And another trouble is created in the lives of the tribal people, and that is the reservation of forests. This reservation of forests is another very dangerous question. I agree that forests must be reserved. But importance should not be given to the forests alone, but much more importance should be given to human lives. What actually happens is this. In our part, for hundreds of years, thousands of people have been staying in the forest area and living on shifting cultivation. Suddenly you declare that particular area as a forest area and you prevent the tribal people from carrying on their jhoom cultivation, and they are evicted from that place. A number of cases have been instituted, the tribal people have been fined and penalised and put into jail. You should not do it, you must not do it. You must respect the life of the people and should not evict them from those places. That is why I am suggesting that this jhoom cultivation by these people should not be prevented unless and until the people of that particular area have been rehabilitated elsewhere.

Till that is done the area should not be declared as a reserved forest area.

Shri Balkrishna Wasnik (Gondia): Sir, the hon. the Home Minister has already expressed his thanks for the weighty report that has been submitted by the hon. Shri Dhebar and the members of his Commission. I would only like to say that we are not doing full justice to this report by discussing it only for four hours, although we have actually given five hours for this discussion because we will be finishing this discussion by half past three.

Looking to the number of recommendations that have been made in this report—they number something like 285—we are not, therefore, giving even one minute per recommendation for this discussion. The report is also very bulky and the first volume comprises of 564 pages. It is so big a report, such an important document, and we are giving such a short time for its discussion. I am really very sorry for this kind of thing.

The Chairman of this Commission has emphatically pressed one point, and that is about the "left-outs". In his letter to the President of India, in paragraph 4, he has said:

> "There is another class of tribals who, through belonging to the same category, has been excluded because of the territorial test that they remain outside particular areas. We can say with some personal knowledge that this distinction while valid in law is without much justification in point of fact."

He has elaborated these things elsewhere also. He has particularly referred to the "left-out" tribes in the Madhya Pradesh area and the Nagpur division of Maharashtra. He has also said that he had in mind to prepare a list, but for lack of adequate data the Commission had dropped the idea. I would request the Government to look into the matter very seriously and see if any left-out tribes could be included in the list and given the facilities.

As the report has pointed out, the tribals are classified on the basis of the areas inhabited by them, as indicated below:

(a) Tribals residing in scheduled areas;

(b) Tribals residing in specified areas; and

(c) Tribals residing in the rest of the State.

Of these, the first two are declared as scheduled tribes, while the third category is known as the "left-out" tribes and they are treated as other backward classes. The Commission say:

> "We have not been able to understand the reason for this glaring differential treatment in respect of the same tribes living in the same region. This gives rise to great dissatisfaction."

Though the Chairman of the Commission and the Members of the Commission in this report have brought out this aspect of differential treatment, I am very sorry to note that the Home Minister, though he spoke for half an hour while intiating the discussion yesterday, did not touch this very important point. I would request the Deputy Minister, who would now be giving the reply, to touch this point and say something about the government policy as to how they propose to deal with this problem.

It is a very important problem, and one of the Members has also just spoken about this. As you know, the scheduled tribes who live outside the scheduled areas are not given the benefits. Suppose there are vacancies in the sefvices. Because they live outside the scheduled areas they cannot be appointed in these vacancies. This is the treatment that is being given to these people. We have pointed this out very often to the Government, but though 14 years have passed after independence, Government have not come forward with any concrete proposal to remove this glaring injustice.

One of the Members speaking yesterday asked why this special treatment should be given to the scheduled tribes. I am rather sorry that there are people in this country and also in this House who, even after so many years of independence and after such a progress that we have achieved not only materially, but otherwise also, come forward with this argument. It is rather surprising that people who sit opposite and talk of progressive things should rather speak out this.

Shri Warior (Trichur): All those sitting opposite cannot be 'progressive'.

Shri Balkrishna Wasnik: I am not speaking of all those Members who are sitting opposite; I was referring to Shri Yashpal Singh. I would request the hon. Members who are against this reservation to go through the proceedings of the Constituent Assembly. It has been discussed there thoroughly

[Shri Balkrishna Wasnik]

and now there is no reason to reopen this issue.

I am glad the Home Minister has talked about increasing the number of tribal blocks from 330 to 450. It is a very good thing.

I would not like to add anything more except that the views which have been expressed by the hon. Home Minister in his speech should be implemented and no stone should be left unturned to achieve the progress in the time-limit that has been specified by the Home Minister.

Shri Rishang Keishing (Outer Manipur): Sir, I am grateful to the Chairman and members of this Commission for submitting such an excellent report. I may say that they have put their heart and soul into the work and they have performed their duty with the utmost sincerity and honesty. As I went through the report, I found many things regarding the problems of tribals. They have made so many recommendations and suggestions for the solution of those problems. In short, I may say that it is a dictionary of the tribal problems and I hope the Government and the people of this country will utilise it to the fullest possible extent.

The most important problem of the tribals is land. As the Commission has rightly pointed out, about 90·5 per cent. of the tribals are agriculturists and out of 173 lakhs of tribal people, 28 lakhs are landless. Perhaps there was a time when land was not at all a problem to the tribals but today they have become landless. I will divide the tribals into two groups; those living in the valley and those living in the hill areas. The land problem is more acute in the case of those who live in the valleys than in the case of those who live in the hill areas, because they are more accessible to non-tribals and non-tribals have exploited them and encroached upon the land of the tribals. The tribal people in the hill areas are never exploited. Before 1947, there was hardly and exploitation, but today after 1½ decades, there has been a lot of exploitation and encroachment upon the tribals. I think this problem has been dealt with by the Commission elaborately and they have made several nice recommendations.

This country stands for socialism, equality and equal distribution of the national wealth amongst the citizens of the country. I think this tribal problem is a challenge to the country. if this country fails to give land to every family of the tribals, India's socialism will completely fail and collapse. I think it is a challenge to the country and to the Government particularly.

As I said, there are 28 lakhs of tribals who are landless. There are crores of acres of wasteland—5,79,57,000 acres, according to the 1951 census. As the Commission has pointed out, preference should be given to the tribals in allotment of such land. Tribals are called the children of the forests. Forest is the mother of tribals. How can you, in the name of reservation, separate these tribals—the children from the mother namely, the forests? Mother and children can never be separated. It is the Government's duty to see that the bonds of good relation between the forests and her children are strengthened.

Today we see that after 1947 so many areas of forest, where the tribals used to have jhum cultivation, have been declared as protected forests. As Shri Dasaratha Deb has pointed out, in Manipur also hundreds of square miles of forests have been declared as protected areas and consequently, the tribals everywhere have acutely felt the pangs of forcible separation of the forests from them. This should not be allowed. I am glad that the Commission has recommended that it should be revised. Government should revise it and see that the lands are released and the tribals are again made the owners of the lands.

Regarding reservation in services, I am of opinion that wherever possible

everywhere, in every State, reservation for the scheduled tribes in Government service should be at least on population basis. In Manipur, at present our tribal population is 32 per cent, but the reservation is only 20 per cent, combined for scheduled castes and scheduled tribes. This is a glaring injustice. At least it should be on population basis and there should be separate reservation for scheduled castes and scheduled tribes.

In the All-India Services also, I am of opinion that sufficient attention has not been paid by Government. It should be taken care of and serious attention should be given to see that tribal boys are selected in these services. I wish to suggest that any tribal boy who appears in the IAS examination of the UPSC and who passes the written examination should be straightaway given appointment, if not in the IAS at least in the Central Secretariat Service. It should be made a rule and the Home Minister should give order to all the State Governments to follow this. Those who have put in at least 5 years service should be immediately promoted to higher posts.

Regarding education, I would like to point out that today university education and secondary education has been made free, but at the bottom, *i.e.*, in the primary stage, education has not been made free in many States. It should be the intention of the Government to see that every private primary school is taken over by Government during the third Plan and every tribal village should have one lower primary school.

Coming to medical facilities, today we are lacking in medical facilities. For example, in Manipur in the hill areas, there are 41 dispensaries, 3 hospitals and 2 primary health centres where doctors are not available. The reason is that there is a dearth of medical practitioners. I would like to suggest that special pay-scales should be fixed for them, they should be given special allowances or three or four advance increments should be paid to them so that they can be induced to extend medical facilities to the people of those areas.

Sir, due to want of time, I cannot make my other points. I feel that the House has done injustice to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Not less than ten hours should have been allotted for discussion on this report, and more people should have been allowed to speak. Every time, whether it is the Report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes or some other thing, we are given a stepmotherly treatment.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Virbhadra Singh.

Shri Basumatari: Sir, nobody from Assam has spoken.

Shri N. N. Patel: Nobody from Gujarat also.

Mr. Deputy-Speaker: Assam is stoutly represented by Shri Basumatari.

Shri Warior: Sir, are all the States given an opportunity to express an opinion?

Mr. Deputy-Speaker: I am trying to do that.

Shri Warior: I am afraid, nobody has spoken from Kerala.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Virbhadra Singh.

Shri Virbhadra Singh: Sir, as the time at any disposal is short, I shall try to be brief. At the very outset I would like to say that the report under discussion is, by and large, a very good report. It is very comprehensive and touches almost all the aspects of tribal life. It is indeed a monumental piece of work, and we would like to convey our sincere thanks to the members of the Commission.

[Shri Virbhadra Singh]

Much has been said about the report and the recommendations made by it. I would only like to draw the attentio of the House to Question No. 132 which appears on page 27 of Volume II of the report. It pertains to the question of discriminatory payment of emoluments and allowances to the government servants or employees who are serving in the remote corners of tribal areas. Sir, there is discrimination in payment of salaries between employees belonging to these tribal areas and those who come from outside. Whereas the employees who come from outside or who are outsiders are entitled to allowances which amount to about 100 per cent. of their salary, the local employees or the tribal people are denied this facility though they might be serving miles away from their homes. I do not understand why this discrimination is made, especially when both the employees whether they are local or tribal or they are from outside are working at the same place and under the same conditions. This discrimination has caused a lot of heart-burning. I think it is against justice, equity and fair play, and it is better that this discrimination is removed forthwith.

The Commission, Sir, have admitted in their report that on account of the changed conditions on the other side of the Indo-Tibetan border our traders have suffered a great setback. Most of our traders there used to trade with Tibet. Now, on account of the changed circumstances there, the trade has come to a stand-still. While admitting this fact, I am sorry to say, the Commission has made no recommendation regarding their rehabilitation. I would like to draw the attention of the Government and this hon. House to the pitiable plight of the traders, especially those belonging to the Kinnaur District of Himachal Pradesh, and I would urge that immediate steps be taken to rehabilitate them before it is too late. The question of their rehabilitation should receive the utmost priority of this Government, because the traders belong to an area which is adjacent to a country which is not very friendly to us and it is in our own interest that these traders should be rehabilitated so that there is no discontent among them.

Also, Sir, the Commission in their report have suggested that additional powers should be given to the Collectors and the Deputy Commissioners. They have said that the Deputy Commissioners or the Collectors should be made overall in-charge of all developmental works connected with tribal welfare at the district level. I am opposed to this suggestion. I feel that our Deputy Commissioners and Collectors are already over-worked, and I do not think that they will be able to do justice to this additional load of work. I am also opposed to this because I feel that this will lead to centralisation. The main purpose of our developmental schemes or welfare schemes is to root out poverty and ignorance, and in order to do that it is essential that there should be maximum co-operation between the people concerned and the executive. In order to elicit this maximum co-operation it is necessary that the people should be taken into confidence and they should be allowed to participate in some way in their own governance and in the execution of their development schemes. If you accept this, then it leads to decentralisation and delegation of powers. Therefore, any suggestion which cuts at the root of this principle and leads to centralisation is most welcome and I am sure the hon. Members of this House will be opposed to such a suggestion. I, therefore, feel that this report lacks the necessary emphasis on the question of decentralisation and delegation of powers, and I urge that this aspect should be kept in mind and should be taken into consideration.

Sir, as I have said earlier, the report is a monumental piece of work, but it is not without its flaws. There are certain flaws which I find it my duty to bring to the notice of the House. During the course of its investigation, the Commission toured very extensively, and wherever it

went it recorded oral evidence of both officials and non-officials. It also received large number of written replies to its questionnaire both from officials and non-officials. But I find, whereas much prominence has been given to the views expressed by officials, I am very sorry to say, the views of common people, the ordinary people, have not found any place in the report.

Shri Sonavane: That is usual.

Shri Virbhadra Singh: This is most unfortunate, because I do not see why the Commission should have chosen to ignore the wishes of the people. After all, public opinion is a very important factor in democracy, and I personally feel that the views expressed by the representatives of the ordinary people should have formed the bulk of the report.

Before I conclude, Sir, I would like to say that I do hope that the report under discussion will in no case be shelved and the recommendations made by the Commission will be implemented so that a time may come when the people of the Scheduled Areas and Scheduled tribes may grow up in stature and may be able to take their part in the life of the nation.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Chandrasekhar.

Shri Basumatari: Sir, nobody has spoken from Assam.

An Hon. Member: From Punjab also. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry, I cannot help it We have to conclude this by 3.30 P.M. when we have to take up non-official business.

An Hon. Member: It may be taken up at 4 O'Clock.

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

15 hrs.

श्री तुलसी दास जाधव (नांदेड) : इस पर बाकी बहस अगले सेशन में करनी चाहिए।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): I do not want to participate in this debate. I only want to submit that when there is such a demand in the House from all sections of the House from the very beginning, it would be only fair that we carry on this motion to the next session. We have done it in the past.

Some Hon. Members: Yes.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): It is very necessary when so many more Members want to participate in the discussion.

Mr. Deputy-Speaker: Yesterday it was decided that we should close this by 3.30 P.M. Today morning also the Speaker made it very clear that the discussion would go on only up to 3 O'Clock when the reply would be given.

Shri Harish Chandra Mathur: In this matter the House is supreme. If the House feels that it should be carried on, there is nothing which can stop the house from taking that course. What is wrong about it? It is not a Bill which has to be passed immediately for Government to take some action.

Mr. Deputy-Speaker: What is the view of the Government?

Shri Rane: Out of the five hours allotted for the discussion of this Report, two hours were taken yesterday. Today the discussion started at 1·30 P.M. If the discussion continues up to 3.30 P.M. only two more hours would be available. So, if the House so desires, it can be carried on to the next session.

Mr. Deputy-Speaker: All right, we will continue this till 3.30 P.M.

An Hon. Member: Half an hour is not sufficient.

Mr. Deputy-Speaker: Today the discussion will go on till 3.30 P.M. Then it will be carried on to the next session.

Shri Warior: I may be allowed to put another proposition. Those States which did not get an opportunity so far may be considered at least in the next session.

Mr. Deputy-Speaker: There do not seem to be any Scheduled Tribes in Kerala. (

Shri Warior: There is no area in any part of India which has no Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

Mr. Deputy-Speaker: Anyhow, I do not have his name with me.

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : मेरा सजेस्टियन यह भी है कि अगले सेशन के फैग-एंड पर इस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Now that the discussion would be going on in the next session, Shri Jaipal Singh will get his opportunity during next session.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West): May I submit that it is not necessary that this discussion should continue today any further? It is the desire of the House that the discussion should be continued in the next session and, if you agree with that view, then the question of extending it till half past three does not arise.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): A perusal of the report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission will reveal that the Commission have done commendable service by giving such a good and instructive report in which they have gone to the minutest details of the problem facing the tribals. We all know that under the able chairmanship of Shri Dhebar, who has got so much love for these people who are living in the backwards areas, in far off tracks, in the forest regions, in a very backward condition socially, economically and politically, who are living under the barbaric conditions, we have got such a wonderful report. We find from that report that these people do not have enough food to eat, proper water to drink or proper cloth to wear. They do not have houses to live in. Sometimes they have to depend on birds and small animals for their food. Shri Dhebar has in his mind all these conditions and compassion and love for these people who are so backward. So, the Commission has gone into the minutest details of every aspect of the problem.

I am very much satisfied with the report except for one fact, and that is enough attention was not paid to the economical, social and political condition and difficulties faced by women. Only a page and a quarter has been allotted to that topic and some mention is made about women enjoying equal rights with men. At the same time, politically they do not participate in the proceedings of the panchayat or the meetings of the tribes.

Here it is very painful for me to bring to the notice of this House that in one district in Andhra Pradesh women are actually kidnapped. What for? Because, there is trading in human flesh, inter-State traffic in tribal women, and they are taken to far off regions and sold. Since this has come to the notice of the State Government, it has been taking some action but I do not know whether it has been brought to the notice of the Central Government. Since the Minister concerned with the tribal areas happens to be also the Minister of Home Affairs, I would appeal to him to see that this sort of thing is stopped immediately and severe action is taken against those people who indulge in such trade in human flesh. This has happened in Mehboobnagar and it has come to the notice of the State Government when one girl who was kidnapped was rescued and returned to her parents.

I was very glad to hear Shri Lal Bahadur Shastri saying that it was his earnest desire that within fifteen years the level of the tribal people should be brought up to the standard of living of the other people. The Commission has elaborately dealt with the conditions of those people and the difficulties faced by them like indebtedness, ignorance, lack of communication, want

of credit facilities etc. So far as indebtedness is concerned, in my own constituency there is a area where there is concentration of tribal people and the moneylenders are the most prosperous people there. If you visit any tribal area you will find that the moneylenders are the most prosperous people. In such areas they go to the tribals and lend them some money in the lean period and take many more times that amount during the harvesting season. According to this Report, the sons of the tribals inherit these debits and they are in perpetual bondage. So, unless we organise some co-operatives, these middlemen and moneylenders cannot be eliminated.

It is stated in the Report that it is also necessary that the State Governments should undertake an enquiry into the incidence of bonded labour. It is suggested that legislation should be passed for treating such agreements as void. It should be looked into.

Development of communications will go a long way in redressing the grievances of those people. For one thing, they will be engaged in that work. Then, people living in the far off tracts are cut away from the entire civilised world. However much you may try to bring them to the level of the other people, unless they see with their own eyes what is the condition in the outside world, it will not be easy to make them change their way of life and make them psychologically adjust themselves to the new conditions. So, communications will not only provide them employment and raise their standard of living by placing more money in their hands, but it will give them quick means of transport. Now they have to walk miles and miles to go to the market to get their daily requirements, which is inhuman.

As far as the construction of roads is concerned, some contractors take them up very leisurely and consequently the works suffer. As for myself, I feel that this entire contractor system should be abolished and labour co-operative societies should be organised. Priority should be given to the formation of labour co-operative societies for undertaking the work of construction of houses as well as roads.

As regards housing the Commission has also suggested that they should be given according to needs and requirements as also the way in which there should be some changes in the pattern of construction of houses.

By the end of the Third Plan, I think, every village has to be provided with a drinking water well. I for one feel that priority should be given in the Tribal areas for digging drinking water wells.

For two days we had a discussion about floods and flood control. In Andhra I know there is this shifting cultivation. I think in other parts of the country also it may be existing. These Tribal people go and cut the forests and cultivate the land. After some time they leave that place and cultivate some other place. This causes soil erosion because the smooth soil is washed off by the rains and all this place is converted into a desert in due course. So, they should be settled at one place. Some co-operative farming societies should also be formed. In my State these people are given five acres of land but we do not know how it changes hands. Within a few days we find that it is in somebody else's name. So, it is better to give them land after forming co-operative farming societies.

I think it would not be proper for me to continue though I have got such a lot to say. I am very much thankful to your for giving me even this opportunity.

Dr. Kohor (Phulbani): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to you for giving me a chance to say

[Dr. Kohor]

something about the tribals in this House today.

The Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission under the chairmanship of Shri Dhebar is a comprehensive one. I welcome it. The members of the Commission deserve commendation because they have very ably and frankly placed on record the abject failure of Central as well as the State Governments in dealing with the problems of the Tribals.

Our beloved Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in writing the foreword of the famous book by Dr. Verrier Elwin on the philsophoy of NEFA has said that the culture, custom, forest rites and religion of the Scheduled Tribes people should be maintained. But even after the completion of the Second Five Year Plan the lot of the Scheduled Tribes is no better than what it was a thousand years ago. My State of Orissa is fortunate enough to have been the field of operation of great men, like, Thakar Bappa and Acharya Vinobha Bhave and lastly Dandakaranya is being operated in my State, particularly in the District of Koraput which is the epitome of the Scheduled Tribes in India, but even then we are what our grandfathers were.

In many parts of the country and in Orissa shifting type of cultivation is done by the Tribal people. The Forest Department and the State Government discourage us from doing this type of cultivation on the ground of soil erosion and wastage of national property. I disagree with them. Even in western countries this type of shifting cultivation is done by civilized people. On the slopes of the Pyreness Mountains which is the border of France and Spain shifting cultivation is the only method of cultivation. In many parts of Africa and on the slopes of Mount Kilimanjaro in Kenya shifting cultivation is going on. If that kind of cultivation is good in one part of the world, I do not think it to be wise enough to abolish this method of cultivation in our country. If this method of cultivation is discouraged by the Government—it may be that the Tribal people are innocent and they do not know how to defend their interest; that is why everybody is preaching a sermon to us—if the Government adopts the policy of abolishing shifting cultivation, then I demand land for land, that is, to be more precise, the Hill people should be given land liberally for the loss that they sustain in losing their present way of life, their home and hearth and, last but not the least, their beloved mountains.

15·17 hrs.

[SHRI SURENDRANATH DWIVEDY *in the Chair*]

It is a very common thing now to see that the District Officers of the Tribal Districts used to give fallow land to people other than the Tribal people instead of giving this fallow land to the Tribals as priority. This practice of neglecting the Scheduled Tribes people in Scheduled Areas should be stopped at once and they should be penalised.

Then I come to the forests. Forests is the economy of the Scheduled Tribe family. From time immemorial we have been born and brought up in forests and the forest gives us employment and food. But now all of a sudden this right has been taken away from us and in return we get half-built homes, one bullock per family and jealously and consequently we are being insulted by the people of the plains. The people of the plains do not know our language, particularly the officers of the Welfare and Public Relations Departments who are supposed to work with us. They also do not know our custom the state of affairs. We have these and do not believe in our religion. My suggestion is that if the Government is sincere in not de-tribing us then these officers should learn the Tribal language and try to be one with us.

Now, I come to education. It is so nice that schools are being opened in my State in many places in the tribal areas, but it is regrettable that these institutions are haphazardly managed by Government. It so happens that these institutions lack in materials, sufficient teaching staff and proper management. There are some newly opened primary and middle schools in which the Government have appointed only the teaching staff, on the condition that the tribal people will supply the required materials for the schools. When the tribal people are living a hand-to-mouth existence, it is quite impossible for them to supply all these requirements. If at all Government are so keen for the upliftment of these tribal people, then I would submit my suggestion that these primary and middle schools should be well equipped with men and material.

In the national enterprise of the Dandakaranya we are seeing that the local Adibasis of Koraput are getting a stepmotherly treatment from the Dandakaranya Development Authorities in comparison with the refugees who have come from East Pakistan. If the East Pakistan refugees are given land, the local Adibasis should also be given the same proportion of reclaimed land, but it is provided in the Commission's report that 2 per cent of the total reclaimed land should be given to the tribals. This discrimination will affect the morale of the tribal people.

Lastly, before I conclude, my only submission is that the tribal problem is a problem of change of heart. Instead of high promises and long lectures, we want good social workers to work among us.

श्री बेसरा (दुमका) : सभापति महोदय, इस सदन में जो ढेबर कमिशन रिपोर्ट विचार के लिये रक्खी गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं । संथाल परगना जिले में आदिवासियों के ज्यादा से ज्यादा बाशिन्दे हैं, लेकिन वहां के लिये जितना रुपया दिया जाता है, उस रुपये को काम में न लाकर वापस कर दिया जाता है । थर्ड फाइव इअर प्लैन में जो रुपया वहां दिया गया है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया गया है । फर्स्ट और सेकेन्ड प्लैन्स में भी जो रुपया दिया गया था वह वापस हो गया । मैं कहना चाहता हूं कि जितना रुपया वहां पर इस प्लैन में दिया गया है वह बहुत कम है और उससे ज्यादा दिया जाना चाहिये ।

वहां पर आदिवासियों के लिये जमीन का ठीक से बन्दोबस्त नहीं हो रहा है । स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जसा कहा गया है उस तरह से नहीं हो रहा है और जमीन की खुदाई के लिये जो रुपया खर्च किया जाता है वह भी ठीक से नहीं किया जाता है । संथाल परगना के जामताड़ा सबडिवीजन में भी आदिवासियों को जो भूमि दी गई है वह ठीक से नहीं दी गई है । माईथान और मसानजोर के बांध के लिये हजारों लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है लेकिन उन लोगों को सही तरीके से रुपया नहीं दिया गया है । उनके लिये नई जमीन का भी बन्दोबस्त नहीं किया गया है । वहां के लोग बिना जमीन के हैं । उनको बदले में जो जमीन दी जाने वाली थी वह भी पूरे तरीके से नहीं दी गई है ।

अब यह सुनने में आ रहा है कि संथाल परगना के अन्दर जामताड़ा के पास कुलडंगा में अजय नदी पर बांध बनवाने के लिये स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश कर रही है । वहां पर बांध बनाये जाने के कारण हजारों आदिवासियों को वहां से हटाया जायेगा लेकिन उन लोगों को ठीक तरीके से जमीन नहीं दी जाती है ।

अजय नदी के बारे में मुझे यह कहना है कि अप्रल के महीने में प्लेनिंग कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है कि बांध कूलडांगा में न होकर सिकटिया में होना चाहिये । मेरा भी यही सजेशन है कि बांध बजाय कूलडांगा में होने

[श्री बेसरा]

के सिकटिया में होना चाहिये क्योंकि कूलडांगा में ११६ मौजे हैं जब कि सिकटिया में उस से कम हैं। कूलडांगा में आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सिकटिया में बांध होना चाहिये क्योंकि वहां उसके होने से आदिवासियों का भी ज्यादा फायदा होगा।

इसके बाद मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को जो वृत्ति दी जाती है वह सब लड़कों को नहीं दी जाती है। किसी लड़के को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, सब लड़कों को वृत्ति मिलनी चाहिये।

बिहार स्टेट द्वारा आदिवासिवों का एक सेवामंडल खोला गया है। उसमें एक बोर्डिंग भी खोला गया है। उस बोर्डिंग में जो लड़के रहते हैं उनका स्कूलों के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। एक आदमी वहां रक्खा गया है, लेकिन वह लड़कों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वहां पर लड़के जरूर रहते हैं लेकिन सुबह और शाम में वहां कभी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिये वह जो बोर्डिंग है वह स्कूल के साथ शामिल किया जाय और स्कूल मास्टरों के द्वारा लड़कों को कंट्रोल किया जाय।

जामताड़ा में १०, १२ हाई स्कूल हैं लेकिन कालेज एक भी नहीं है और लड़के वहां से दूर पढ़ने के लिये कालेज नहीं जा सकते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि इसलिये कि जामताड़ा में सूटेबल पढ़ाई हो सकें, वहां एक कालेज खोला जाना चाहिये और आदिवासियों के लड़कों को शिक्षा दी जानी चाहिये।

संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वह आदिवासियों का एरिया है। उसके लिये सुनने में आता है कि उसे दो भागों में राज्य सरकार बांटना चाहती है। मेरा यह विचार है कि उसको दो भागों में नहीं होना चाहिये बल्कि जैसा आज है वैसे ही रहना चाहिये। यही बात ढेबर कमिशन की रिपोर्ट में भी दी गई है।

ब्लाक्स के जरिये जो काम आदिवासियों को दिया जाता है वह अच्छी तरह से नहीं होता है। वह लोग ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। इसलिये अगर वहां पर कोई काम होना है जमीन की खुदाई वगरह का तो लाक्स के बजाय जो आदिवासियों के जमींदार आदमी हैं जिनको चासी कहा जाता है, उनको लेकर एक कंट्रेक्टर बना दी जाय और उसके जरिये से काम कराया जाय। ऐसा किया जायेगा तभी आदिवासियों का भला हो सकता है,नहीं तो नहीं।

सभापति महोदय : आप क्या अभी और बोलना चाहते हैं ?

श्री बेसरा : जी, हां।

सभापति महोदय : इस पर फिर बहस शुरू होगी तब बोलिएगा।

15·30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra) I beg to move:

"That this House agrees with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on the 5th September, 1962".

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on the 5th September, 1962".

The motion was adopted.